

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



सर्व संकल्प से
100% सिद्धि तक



सर्व संकल्प से
100% सिद्धि तक



**पर्यावरण संरक्षण,
जन-जन में जागरण**

सारांश

मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के समय से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक, उनके शासन में जो निरंतरता दिखाई देती है, वो है पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास। उनके नेतृत्व में पहले गुजरात और अब पूरे देश में एक ओर जहां विकास के काम में तेजी आई है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण पर भी भरपूर जोर दिया जा रहा है। आज देशभर के लोग पर्यावरण को सिर्फ नुकसान से ही नहीं बचा रहे, बल्कि उसकी रक्षा करते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।

बीते आठ वर्षों में भारत Climate Change के खिलाफ लड़ाई में एक Global Leader के रूप में उभरा है। एक ओर Emission Reduction और Global Climate Change समझौते पर बातचीत, तो दूसरी ओर Renewable Energy के भरपूर इस्तेमाल तक, देश पर्यावरण संरक्षण के लिए हो रहे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की अगुआई कर रहा है।

जब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली, उस समय वैश्विक स्तर पर भारत को जलवायु परिवर्तन पर होने वाली चर्चा में एक बाधा के रूप में देखा जा रहा था। हलांकि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जिस समाधान की जरूरत थी, प्रधानमंत्री उसके साथ सामने आए। इसी का परिणाम है कि आज भारत सिर्फ दर्शक और निष्क्रिय भागीदार होने के बजाय जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक एजेंडा को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के 'Climate Justice' के सिद्धांत ने COP 21 से यह सुनिश्चित किया है कि जलवायु पर होने वाली वार्ताओं में Equity Concerns को नजरअंदाज नहीं किया जाए। भारत का 'निष्पक्ष समझौते' पर जोर है और

वह वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों की आवाज के रूप में उभरा है। भारत की सक्रिय भागीदारी ने सुनिश्चित किया है कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती हैं, साथ ही जलवायु से संबंधित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी देश सफल हो रहा है।

पिछले साल Glasgow में आयोजित COP-26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए दुनिया को 'पंचामृत' का मंत्र दिया। यह एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ एक ऐसा रास्ता तैयार करता है, जिसका पूरा वैश्विक समुदाय बार-बार अनुसरण कर सकता है। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए 2070 को Net-Zero Emissions के लिए भारत का Target Year घोषित किया।

मोदी सरकार ने जहां वैश्विक स्तर पर प्रयास किए, वहीं देश में भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। मोदी सरकार पर्यावरण कानून को लागू करने में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर दे रही है। इससे न सिर्फ सरकार में विश्वास पैदा हुआ है, बल्कि यह भी सुनिश्चित हुआ है कि Sustainable Development संभव है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए मोदी सरकार के उल्लेखनीय कार्यों के परिणामस्वरूप कई सराहनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं। देश में Forest Cover तेज रफ्तार से बढ़ा है। पिछले एक दशक में भारत में बाघों की आबादी बढ़कर दोगुनी से भी अधिक हो गई है। जहां कई देश जलवायु से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे, वहीं भारत ने समय सीमा से बहुत पहले ही लक्ष्य प्राप्त कर लिया। भारत ने COP-21 में Non-Fossil Sources से बिजली क्षमता का 40 प्रतिशत प्राप्त करने

का लक्ष्य तय किया था। इसे नौ साल पहले ही प्राप्त कर लिया गया।

मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'नमामि गंगे' ने पवित्र नदी के प्रदूषण को कम करने में सफलता हासिल की है। इससे कई स्थानों पर पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के दिल के काफी करीब है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें मिले उपहारों की नीलामी से जो धन प्राप्त हुआ, उसे उन्होंने 'नमामि गंगे' कार्यक्रम को दान कर दिया।

पिछले आठ वर्षों में Cleaner और Renewable Sources की दिशा में तेज बदलाव हो रहे हैं। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में Renewable energy में वृद्धि दर भारत में सबसे अधिक रही है। 2014 की तुलना में Clean Energy की हमारी स्थापित क्षमता दोगुनी से भी अधिक हो गई है। Renewable Energy सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन से टैरिफ में भारी कमी आई है। इसके अलावा उजाला योजना के तहत 36 करोड़ से अधिक LED बल्ब वितरित किए गए हैं। इससे हजारों करोड़ रुपये की बचत हुई है और भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका गया है।

Clean और Healthy Environment के लिए प्रधानमंत्री के विजन में जनभागीदारी का अहम स्थान है। स्वच्छता से लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने तक, उन्होंने लोगों को पर्यावरण में योगदान देने और जीवनशैली में बदलाव लाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया है। इस उद्देश्य को जनआंदोलन का रूप देकर उन्होंने तय किया कि इसका स्थायी और बड़े पैमाने पर असर हो।

* * *

मुख्य बातें

2018 के गणना के अनुसार भारत में बाघों की आबादी दोगुनी हुई

नमामि गंगे मिशन के तहत
30,853 करोड़ रुपये
से अधिक की परियोजनाएं लॉन्च

भारत ने
2070 तक नेट-जीरो इमीशन
प्राप्त करने का संकल्प लिया है

भारत ने निर्धारित समय से
9 साल पहले COP 21 लक्ष्य
हासिल कर लिया

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता
दोगुना से अधिक

2014 से सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता
1,900% बढ़ी है

2014 के बाद से सौर ऊर्जा दरों में लगभग
70%
की कमी

पीएम-कुसुम के तहत लगेगे
20 लाख
सोलर पंप

उजाला योजना के तहत
36 करोड़
एलईडी बल्ब वितरित

10 से अधिक भारतीय समुद्र तटों को अब
ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट

जम्मू और कश्मीर का पल्ली भारत का पहला 'कार्बन न्यूट्रल पंचायत' है

विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क
(2,200 मेगावाट से अधिक) भादला, राजस्थान में शुरू

याद रखने वाली बातें

सतत विकास सुनिश्चित करना

- मोदी सरकार ने दिखाया कि **विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण** भी संभव है।
- मोदी सरकार में पर्यावरण कानूनों में हुए सुधार ने **Compliance और Ease of Doing Business दोनों को प्रोत्साहित किया**

वैश्विक जलवायु परिवर्तन वार्ताओं को भारत दे रहा आकार

- भारत पहले की तुलना में आज Climate Change संबंधी वार्ताओं में

Leading Voice बना

- भारत 'Climate Justice' को वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित चर्चा के केंद्र में लाया।
- प्रधानमंत्री मोदी की **'Panchamrit' और 'LIFE यानि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट'** की पहल भारत को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक रोल मॉडल के रूप में सामने लाया है।

भारत के Green Landscape को बदल रही है जनभागीदारी

- Big Targets और

Speedy Achievement भारत की Renewable Energy Policy की पहचान

- 2014 के बाद सौर ऊर्जा क्षमता में 20 गुना वृद्धि हुई
- प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण संरक्षण में जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया
- स्वच्छ भारत से लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने तक, लोगों को प्रेरित कर दैनिक आदतों में स्वैच्छिक बदलाव लाए

* * *

क्या आप जानते हैं?

ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने 'लाइफ' के रूप में दुनिया के सामने 'वन-वर्ड मूवमेंट' पर जोर दिया, जिसका मतलब 'लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट' है।

प्रधानमंत्री ने दुनिया से **पर्यावरण अनुरूप जीवन शैली' यानी LIFE** को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक वैश्विक मिशन बनाने का आह्वान किया। इसका विजन न केवल ऊर्जा उत्पादन बल्कि ऊर्जा संरक्षण और बेहतर जीवन पर भी जोर देता है। इन समाधानों में ऊर्जा कुशल एसी, गीजर, हीटर और ओवन शामिल हैं।

सरकार के बड़े काम

पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पंचामृत

2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करना

2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से कम करना

2030 तक अक्षय ऊर्जा से अपनी आधी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेंगे

2030 तक 500 गीगा वाट की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता

2070 तक शून्य लक्ष्य हासिल करना- वैश्विक जलवायु परिवर्तन नेतृत्वकर्ता होगा भारत



उजाला एलईडी से भारी बचत

एलईडी बल्ब वितरित 36.79 करोड़

प्रति वर्ष ऊर्जा की बचत 47,785 किलोवाट

प्रति वर्ष लागत बचत रु.19,114 करोड़



स्वच्छ गंगा का सपना साकार हो रहा है



नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में एक प्रमुख पहल के रूप में शुरू किया गया

- 30,780 करोड़ रुपए की लागत से 357 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें से 178 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता में वृद्धि से नदी स्वच्छ हुई है
- डॉल्फिन जैसी जलीय प्रजातियां लौट रही हैं।
- नदी में फेंके जाने वाले लाखों लीटर प्रदूषक पदार्थ रुक गए हैं।

कार्यवाही

बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की भारत की कहानी

पीएम मोदी ने दुनिया से वादा किया था कि भारत 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता तक पहुंच जाएगा

महत्वाकांक्षी? लेकिन भारत पहले से ही रिकॉर्ड गति स्थापित कर रहा है

गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा कुल स्थापित क्षमता का 40.1% है

2014 के बाद से भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में **126%** की वृद्धि हुई है!

मार्च 2014 तक

72.22 GW →

भारत की स्थापित स्वच्छ ऊर्जा क्षमता

केवल 8 वर्षों में,

163.33 GW

के साथ भारत दोगुना से अधिक

यहां जानिए कि भारत कैसे अक्षय ऊर्जा में एक उभरता हुआ वैश्विक नेता है!

- भारत के पास अब विश्व की **चौथी सबसे बड़ी** स्वच्छ ऊर्जा क्षमता है
- भारत के पास **चौथी सबसे बड़ी** स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है
- भारत के पास 5वीं सबसे बड़ी सौर संस्थापित क्षमता है

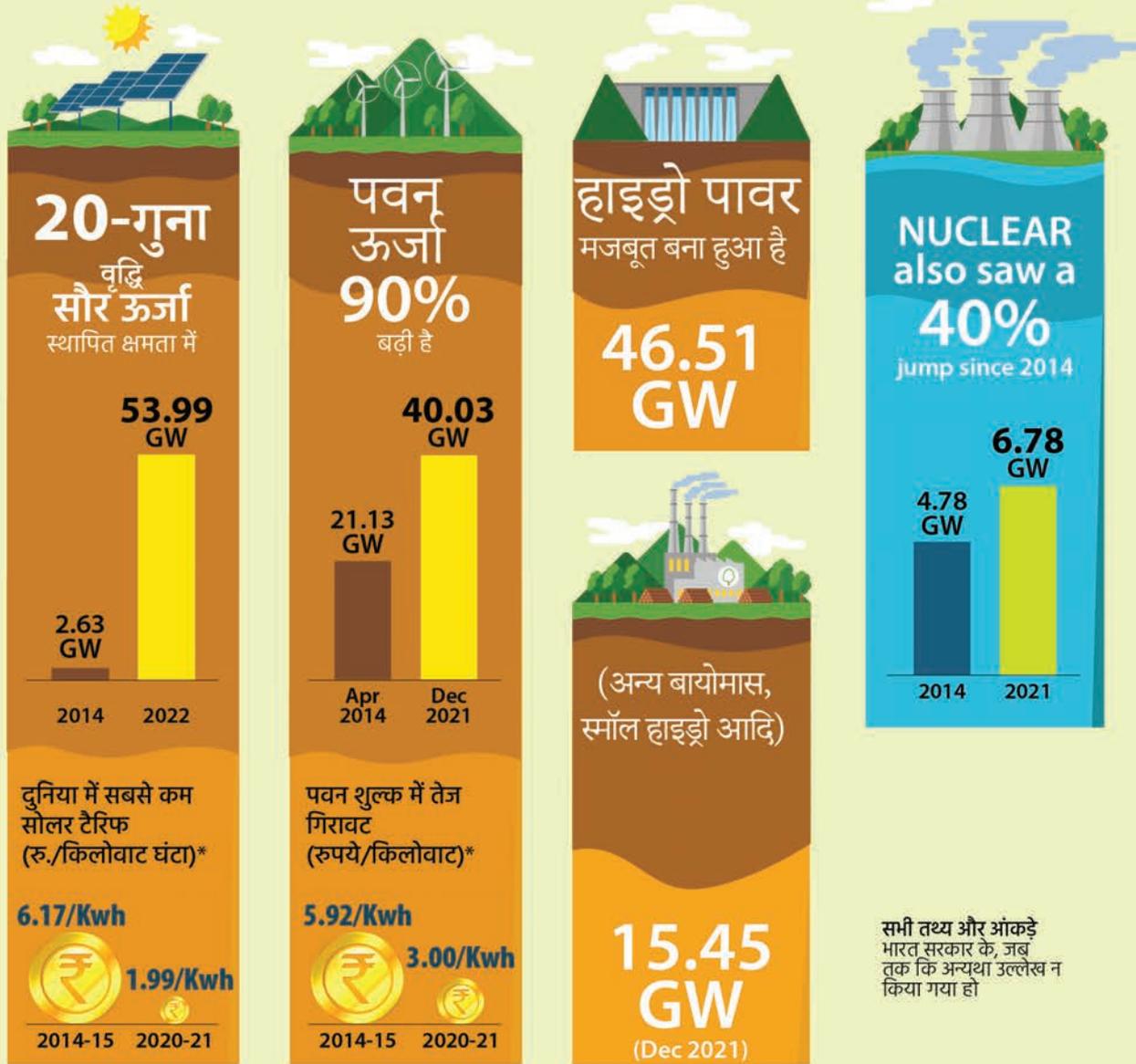
अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक निवेश और तैनाती के अवसरों के आकर्षण पर देशों को रैंक करता है। देखिए भारत की रैंक में कैसे उछाल आया...



FEBRUARY
2014

OCTOBER
2021

इस भारी उछाल के पीछे कारण क्या है?



केवल क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। उसे अपनाना भी मायने रखता है। इसलिए दरों में भी कमी की गई है।

भारत उदाहरण के साथ अग्रणी:

गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% ऊर्जा का सीओपी21 लक्ष्य निर्धारित समय से लगभग एक दशक पहले हासिल किया गया

भारत सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के मार्ग पर चल रहा है

वैश्विक परिवर्तन में अग्रणी:

प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाने की वैश्विक पहल की अगुवाई की जिसमें 86 सदस्य देश हैं

हेडलाइन्स

 **Hindustan Times**

'One Sun, One World One Grid': PM Modi calls for global solar grid at COP26

Nov 03, 2021 |

Business Standard

PM Modi donates Rs 1.4 crore Seoul Peace Prize money to Namami Gange fund

: February 22, 2019

THE ECONOMIC TIMES | Industry

US joins India-led International Solar Alliance as 101st member

Nov 11, 2021

THE ECONOMIC TIMES | News

Dec 28, 2020

Budget 2020: Govt expands PM KUSUM scheme for solar pumps, targets to cover 20 lakh farmers

ET Energyworld.com

From The Economic Times

India's solar power capacity has grown 18 times in seven years: Minister

December 07, 2021

HT Hindustan Times

PM Modi delivers India 'panchamrit' gift at COP26 to fight climate change: Five commitments in detail here

Nov 01, 2021

Bloomberg

Asia Edition ▾

Modi Outshines Biden on Glasgow Climate Stage: COP26 Daily

1 November 2021

The Guardian
News website of the year

Narendra Modi pledges India will reach net zero emissions by 2070

Mon 1 Nov 2021

8 वर्ष, 8 मोदी योजनाएं,

मोदी सरकार की 8 प्रमुख योजनाएं जिन्होंने

पीएमजेडीवाई: प्रधानमंत्री
जन-धन योजना

2014

बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक
सार्वभौमिक पहुंच का विस्तार

45.21 करोड़
बैंक खाते

स्वच्छ भारत मिशन

2014

सभी ग्रामीण घरों में शौचालयों का विस्तार

11.23 करोड़
घरेलू शौचालयों का निर्माण

पीएमएसबीवाई:
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

2015

भारत सरकार की दुर्घटना बीमा योजना

28.18 करोड़
नागरिक नामांकित

8 साल
सेवा, सुशासन और
गरीब कल्याण

पीएमएमवाई: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

2015

छोटे व्यवसायियों को 10 लाख रु.
तक का माइक्रो-क्रेडिट लोन

34.93 करोड़
लोन स्वीकृत

- लॉन्च वर्ष
- लाभ का वितरण
- लाभार्थियों की संख्या

8 करोड़ से अधिक लाभार्थी

8 करोड़ से अधिक लोगों का जीवन बदल दिया है

पीएम-किसान: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

2019

किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष
का सुनिश्चित नकद ट्रांसफर।

12.04 करोड़
किसान

प्रधानमंत्री आयुष्मान
भारत योजना कार्ड

2018

मुफ्त स्वास्थ्य बीमा
कवरेज तक पहुंच

17.9 करोड़
स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी

8 साल
सेवा, सुशासन और
गरीब कल्याण

पीएमयूवाई: प्रधानमंत्री
उज्ज्वला योजना

2016

खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन
के लिए मुफ्त एलपीजी
कनेक्शन

9 करोड़
महिलाएं

पीएमजेजेबीवाई: प्रधानमंत्री
जीवन ज्योति बीमा योजना

2015

भारत सरकार की जीवन बीमा योजना

12.65 करोड़
नागरिक नामांकित



सत्यमेव जयते

भारत सरकार